कॉरपोरेट के नजरिए से देखिए बंगाल चुनाव

गिरीश मालवीय

आपने कभी ध्यान से सोचा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या खास है जो पिछले कई सालों से भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा कर यहाँ के राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में करने मे इतनी आतुर नजर आती है?

राजनीतिक विश्लेषण तो बहुत से समीक्षक करते हैं लेकिन वे नही बताते कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीतना पूर्वोत्तर भारत और उसके जरिए पूरे उत्तर पूर्वी एशिया के देशों तक अडानी, अम्बानी के कॉरपोरेट गैंग की पकड़ बना देगा।

दरअसल, बंगाल चुनाव में भाजपा के पीछे अडानी, अम्बानी की कॉरपोरेट लॉबी पूरी ताकत से धन बल के साथ जुटी हुई है, साम दाम दंड भेद का हर सम्भव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है।

दस साल पहले सोची समझी रणनीति के तहत वाम का किला ढहाया गया और अब उस किले को ढहाने वाले को ढहाया जा रहा है। वाम के किले में सेंध ममता ने लगाई और अब ममता के किले में सेंध बीजेपी लगा रही है।ममता को 21 सदी के पहले दशक में कॉरपोरेट घरानों और नए उदार अमीरों का अंध समर्थन मिला था लेकिन 2021 में तो असली डाकू आए हैं।

अभी तक वाम के लाल रंग के कारण बंगाल एक ऐसा मजबूत गढ़ था जहाँ अडानी, अम्बानी अब तक अपना खेल खुल कर नही खेल पा रहे थे। इसलिए अडानी, अम्बानी गैंग के लिए 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतना करो या मरो जैसा प्रश्न है। वह बंगाल को भी देश की 'मुख्य धारा' में शामिल करने के लिए हर कीमत देने को तैयार है। बीजेपी का विकास "मॉडल" अब बंगाल में भी दोहराए जाने को तैयार है

हम सब जानते हैं कि अडानी का कब्जा पूरे देश के तटीय इलाक़ों पर हो गया है, अडानी ग्रुप के पास देश का सबसे बड़ा पोर्ट नेटवर्क है। पश्चिमी तट के जितने भी प्रमुख बन्दरगाह हैं, वह मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उसके नियंत्रण में आना शुरू हो गए थे। 2014 से 2019 के दौर में पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुके हैं। देश के पूर्वी तट पर भी एक एक करके बन्दरगाह वह अपने कब्जे में कर रहा है। अब सिर्फ बंगाल का हल्दिया पोर्ट ही ऐसा है, जहाँ उसे राज्य सरकार के प्रतिकार का सामना करना पड़ता है। हल्दिया पोर्ट से नेपाल तक को माल सप्लाई होता है।

अडानी अम्बानी इस वक्त बंगाल को साउथ-ईस्ट एशिया और नॉर्थ-ईस्ट इंडिया को जोड़ने के लिए एक गेटवे की तरह देख रहे हैं।

बिहार में कॉरपोरेट की पहली जीत हो चुकी है। भाजपा नीतीश कुमार को इस चुनाव में वह सबक सिखा चुकी हैं। अब भाजपा बड़ा भाई है और जेडीयू छोटा भाई। नीतीश के पर कतरे जा चुके हैं। वहाँ वे बीजेपी के रबर स्टैंप के बतौर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं।

अडानी समूह 2018 में कह चुका है कि वह पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कंपनी की खाद्य तेल रिफाइनरी की क्षमता को दोगुना करने के लिए 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। मुकेश अंबानी भी पश्चिम बंगाल में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान कर चुके हैं।यह निवेश पेट्रोलियम और खुदरा कारोबार में किया जाएगा।

वाराणसी से हल्दिया के बीच गंगा में विकसित हो रहे जलमार्ग पर अडानी ग्रुप 10 जलपोतों का संचालन करने जा रहा है। पटना टर्मिनल तक भी वह दो हजार टन क्षमता के जहाज चलाना चाहता है।

इसके अलावा उन्हें एक पूरी तरह से अनछुआ व्यापार क्षेत्र मिलने जा रहा है, भारत को जमीन के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने की योजना है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के सहयोग से ट्राई लेटरल हाईवे का निर्माण चल रहा है। अब थाईलैंड और भारत के मध्य व्यापार बढ़ाने के लिए थाईलैंड के रानोंग बंदरगाह से भारत के चेन्नै व अंडमान को भी समुद्र मार्ग से जोड़ने की योजना है।

बांग्लादेश भी तीनों तरफ से पूर्वोत्तर भारत से घिरा हुआ है यानी वहाँ भी व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और मोदी अपने हर दौरे में अडानी अम्बानी के लिए वहाँ जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करते आए हैं।

साफ है कि अडानी अम्बानी जैसे गुजराती पूंजीपतियों के लिए बंगाल चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें पूर्वोत्तर भारत और उस रास्ते के जरिए दक्षिण-पूर्व एशिया तक पैर जमाने का मौका मिल जाएगा।

इसी के लिए हिंदुत्व की जमीन तैयार की जा रही है। जब बिहार में कॉरपोरेट पूंजीपतियों ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए तो उन्होंने बेगुसराय जिले के सिमरिया में कुंभ के नाम एक बहुत बड़ा धार्मिक इवेंट करवाया था। इस इवेंट में गुजरात के कई उद्योगपतियों ने अपना पैसा लगाया था। इस पैसे से बीजेपी ने वहां वोटों की तगड़ी फसल काटी है। इसी पैटर्न पर पिछले कुछ सालों से बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है, और जमकर पैसा झोंका गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पैसे से मिली सफलता हम देख चुके हैं और 2021 में भी भाजपा लोकसभा चुनाव जैसी सफलता की उम्मीद कर रही है।

बंगाल चुनाव में भाजपा के पीछे से जो अडानी अम्बानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों का एजेंडा है, उसे एक बार ध्यान से समझना जरूरी है।

ऐसा आपने कितनी बार देखा है कि निवर्तमान 4 सांसदो को केंद्र का सत्ताधारी दल विधायक बनाना चाहता हो? बंगाल पर नज़र तो डालिए। हालाँकि ममता बनर्जी भी पूँजीपतियों के हितों को ही संरक्षित करती हैं लेकिन उनके कैंप में अडानी, अम्बानी नहीं हैं। खेल बहुत गहरा है।

आपकी बीमारी अमीरों का सबसे बड़ा हथियार

डॉ सलमान अरशद

संसदीय सियासत में मौजूद सभी पार्टियों की असली ताकत जनता के दिलों में उठी असमानता की दीवार है। इस दीवार की बुनियाद सर्वोच्चता का वो भाव है जो हर किसी को जातीय, नस्लीय और धार्मिक आधार पर खुद को दूसरों से, या कुछ लोगों से उच्च मानने का भाव पैदा करता है।

भारत में इसका सबसे स्पष्ट रूप जातियों के श्रेणीक्रम में देख सकते हैं। कहने के लिए तो चार वर्ण हैं लेकिन उच्च वर्ण ब्राह्मण भी एक नहीं है, उनमें भी श्रेष्ठता का श्रेणीक्रम है। सबसे निम्न वर्ग शूद्र है, शूद्रों का एक हिस्सा अब पिछड़ा वर्ग कहलाता है। (कुछ लोग इसे कुछ और कहेंगे, लेकिन इससे मूल तथ्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।) लेकिन दलितों पर जुल्म के मामले में ये पिछड़ा भी ऊपर के सभी वर्गों के साथ हो लेता है। फिर दलितों में भी ये श्रेणीक्रम है।

इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भी सैयद से लेकर मेहतर तक के श्रेणीक्रम में हैं, इनमें हिन्दुओं जैसी छूतछात तो नहीं है लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता इनमे भी नहीं होता। ऊपर से फिरकों का अपना अलग फंडा है, ये तो जातीय बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है।

पिछले लगभग 125 सालों में भारत में हिन्दू बनाम मुसलमान का मुद्दा खड़ा किया गया, उम्मीद की गई कि इससे व्यापक हिन्दुओं की एकता बनेगी, बनी भी और लगभग 100 साल की मेहनत और अरबों रुपये के खर्च के बाद लोकतांत्रिक तरीके से एक ऐसी सरकार वजूद में आई जिसे हिन्दुओं की सरकार कहा गया। लेकिन ये हिन्दू एकता भी संतरे की तरह है, हिंदुत्व का छिलका हटाइये तो भीतर वही जातियों के फांक हैं जो एक दूसरे से जुड़ने को तैयार नहीं हैं।

इंसानी दिलों में ये बंटवारा पूरी दुनिया में है। लेकिन असली लड़ाई ये नहीं है। दरअसल दुनिया में जितनी भी संपदा है उसे मेहनत करने वालों ने सृजित किया है, लेकिन इस दौलत के मालिक वो हैं जिन्होंने इन मेहनत करने वालों को नियोजित किया है। ये दौलतमंद हर हाल में सारी संपदा अपनी तिजोरी में क़ैद रखना चाहते हैं और डरते हैं कि दुनिया के ग़रीब लोग एक दिन इनको और इनकी चाल को पहचान न लें। इससे बचने के लिए इनकी ओर से धर्म गुरू आपको इस जन्म और उस जन्म की कहानियां सिखाता है। मुल्ला जन्नत, दोज़ख, शराब और हूरों की कहानियाँ सुनाता है, और भी बहुत कुछ। मकसद सिर्फ इतना है कि इस ज़मीन पर, इसी जीवन में, जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश आप न कर पाएं।

यही नहीं, दौलत के लुटेरे अलग अलग जातियों और धर्मों के नेता और बुद्धिजीवी खड़े करता है, उनको पैसे और सुविधा देता है, अलग अलग धर्मों और जातियों के ये नेता आपकी ज़िंदगी बेहतर करने का वादा करते हैं। अमीरों की खड़ी की गई ये फौज़ आपस में भी लड़ती है ताकि आपको भी लगे कि ये अलग अलग हैं।

अब दिक़्क़त ये है कि हजारों सालों में आपको बांटने के लिए जो धर्म, नस्ल और जाति की दीवार खड़ी की गई है, उसे आपने अपने सीने से लगा लिया है, उसके लिए जीने मरने को स्वाभिमान मान लिया है, आपकी ये बीमारी अमीरों का हथियार है। एक बार काले बनाम गोरे, ऊंची जाति बनाम नीची जाति, ये धर्म बनाम वो धर्म की दीवार गिरा दीजिये, खुद को सिर्फ इंसान मानिए और हर इंसान को अपना, फिर देखिए कि जीवन को सुंदर बनाने का रास्ता कैसे खुद बखुद आपके सामने आ जाता है। आज हिन्दुओं की सरकार भी अगर 10 अमीरों के सामने करोड़ो हिन्दुओं को रगेदे हुए है तो इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में हर राजनीतिक सत्ता सिर्फ अमीर की सेवा करती है।

मोदी सरकार रोज़ रोज़ हो रहे आंदोलनों से अगर ज़रा भी परेशान नहीं है, तो उसका कारण जनता के दिलों में पैदा हुई वो दीवार ही है, जिसकी बात ऊपर की गई है, और जिसकी मज़बूती पर सत्ताधारी वर्ग को यकीन है। दिल करे तो इस पहलू पर सोचिये !

यूएन में गूंजी किसानों की आवाज़, दर्शन पाल ने कहा- हमारी सरकार से घोषणापत्र का सम्मान करने को कहे यूएन

जनचौक ब्यूरो

नई दिल्ली, किसान आंदोलन की आवाज यूएन तक पहुंच गयी है। और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि किसानों ने खुद किया है। इसके लिए किसान नेता डॉ. दर्शनपाल को बुलाया गया था।

इस मौके पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को भारत सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कृषि क़ानूनों के प्रति किसानों की चिंता, अहित और असुरक्षाबोध से संयुक्त राष्ट्र को परिचित कराया है।

डॉ. दर्शनपाल ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधाकिर परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा नाम डॉ. दर्शन पाल है और मैं भारत का एक किसान हूँ। मैं आभारी हूँ कि संयुक्त राष्ट्र हमको सुन रहा है। हम भारतीय किसान अपने देश से प्रेम करते हैं। और हमको उस पर गर्व है। हम संयुक्त राष्ट्र पर भी गर्व का अनुभव करते हैं। जिसने किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, कि दुनिया भर के छोटे किसानों के हितों की रक्षा हो।

उन्होंन अपने वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र का हवाला देते हुए कहा कि मेरे देश ने भी इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और कई सालों तक, इसमें किसानों के हित सुरक्षित रहे। इसमें किसानों की फसल के उचित मूल्यांकन के द्वारा उनकी गरिमापूर्ण आजीविका सुनिश्चित करना भी हिस्सा था। जिसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कहते हैं। हमारे पास एक अच्छा बाज़ार तंत्र था जिसका प्रयोग ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में होता था। और साथ ही हम अदालत में भी जा सकते थे। नये कृषि क़ानूनों में ये सब हमसे छीना जा रहा है। ये क़ानून हमारी आय दोगुनी नहीं करने वाले हैं। जिन कुछ राज्यों में पहले ऐसी ही नीति लागू की गई है उन्होंने किसानों को गरीबी के चपेट में आते देखा है। वे अपनी ज़मीनें गँवाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमको सुधार तो चाहिए, पर ऐसे सुधार नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि "यूएन का घोषणापत्र देशों को बाध्य करता है कि नई योजना-नीति लागू करने से पहले, किसानों से सलाह लें।

हम संयुक्त राष्ट्र से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सरकार से घोषणापत्र का सम्मान करने को कहें। कि सरकार क़ानून वापस ले। और किसानों से बात करे। और फिर किसान के हित में नीतियां बनाकर लागू करे। साथ ही ऐसी नीतियां जो कि पर्यावरण के भी हित में हों। जैसा कि किसानों के लिए घोषणापत्र में उल्लिखित है।"

पहली से आठवीं की परीक्षाएं 26 मार्च से

चण्डीगढ़ (म.मो.) । हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को पहली से आठवीं कक्षा तक की डेटशीट जारी कर दी है। सभी परीक्षाएं 26 मार्च से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन होंगी। सिर्फ पहली और दूसरी कक्षा का ऑफलाइन मौखिक टैस्ट होगा।

तीसरी कक्षा से लेकर आठवीं तक परीक्षाएं ऑनलाइन 'अवसर ऐप' के जरिए होंगी। ऑनलाइन ऐप सुबह 5:00 बजे से लेकर रात्रि 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। डेटशीट में कक्षा छठी से आठवीं तक संस्कृत, उर्दू और ड्राइंग का उल्लेख नहीं है। ये परीक्षाएं टीचर अपने स्तर पर ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके लिए वाट्सऐप, जूम आदि के जरिए भी कराई जा सकती है। यह जानकारी सहायक शिक्षा निदेशक ने दी।